

सम्पादकीय

नगालैंड की घटना के सबक

नगालैंड में सुरक्षाबलों की गोलीबारी से एक जवान समेत 15 लोगों की मौत से एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों, सुरक्षा बलों की गतिविधियों और खुफिया एजेंसियों की सक्षमता पर सवाल खड़े होते हैं। अगर सर्वेदनशील सरकार होती तो अब तक गृहमंत्री इस्टीफे की पेशकश कर चुके होते, लेकिन मौजूदा सरकार में गृहमंत्री बयान देने में यकीन रखते हैं। हालांकि उनके बयान देने से न मृत लोग जिंदा हो सकते हैं, न सुरक्षा बलों और आम जनता के बीच विश्वास बहाली हो सकती है। नगालैंड की घटना इस बात का प्रमाण है कि पूर्वोत्तर में हिंदुत्ववादी एजेंडे को लागू कर भाजपा ने अपने पैर तो पसार लिए, लेकिन यहाँ के नाजुक हालात संभालने में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही है। पहले असम-मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ, जो आजाद देश में अभूतपूर्व घटना थी। इसके बाद त्रिपुरा में बांग्लादेश मामले के कारण सांप्रदायिक तनाव कायम हुआ और अब नगालैंड में सुरक्षा बलों ने उत्तरवाद से लड़ाई के नाम पर अपने ही नागरिकों को निशाना बनाया, पहले भूल से और उसके बाद दमनकारी अंदाज में। 4 दिसंबर को नगालैंड के मोन जिले के तिरू और ओटिंग गांव के कुछ लोग कोयला खदान में काम करने गए। लेकिन शाम तक छह युवक वापस नहीं लौटे, तो उनके परिजनों और गांव के लोगों ने तलाश शुरू की। ओटिंग में ही एक पिकअप वैन में 6 युवकों के शव लथपथ पड़े मिले। पहले तो माजरा समझ नहीं आया, बाद में पता चला कि यहाँ पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की थी। इसके बाद वहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण इकज हो गए। नाराज, बेकाबू भीड़ ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन उग्र भीड़ शांत नहीं हो रही थी। इस दौरान दोबारा फायरिंग हुई जिसमें फिर कुछ लोगों की मौत हो गई।

गैरतलब है कि मोन जिले की सीमाएं म्यांगार से मिलती हैं और प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट कार्डिसिल औफ नगलैंड-के (एनएससीएन-के) के युंग ऑंग धड़े की गतिविधियां यहीं से संचालित होती हैं। सेना को खुफिया सूचना मिली थी कि यहां कोई उग्रवादी गतिविधि की आशंका है, जिसके आधार पर सेना ने कार्रवाई की। लेकिन इस कार्रवाई में अपने ही नागरिकों को सेना ने निशाना बनाया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में रोष की लहर दौड़ना स्थानीय बन गया है।

स्वाभाविक है। जनता के आक्रांश को देखत हुए अब यहा कफ्यूलगा दिया गया है, कई जगह इंटरनेट पर पाबिदियाँ हैं। नगालैंड पुलिस ने भारतीय सेना के 21 पैरा विशेष बलों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में नगालैंड पुलिस ने स्पष्ट रूप स कहा है कि पैरा स्पेशल बलों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था, न ही कोई पुलिस गाइड लिया था। सेना अपनी कार्रवाई के पीछे 'गलत पहचान' को कारण बता रही है, लेकिन प्राथमिकी में पुलिस ने 'सुरक्षा बलों की मंशा नागरिकों की हत्या और घायल करना' बताया है। नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने प्रदेश में पांच दिनों के शोक का ऐलान किया है। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियु ने इस घटना पर दुख जताते हुए एसआईटी की जांच की घोषणा की है और मृतकों के परिजनों के लिए पांच-पांच लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सेना ने भी घटना को खेदजनक बताते हुए 'कोर्ट ऑफ इन्कवायरी' का आदेश दिया है। नगालैंड की इस घटना के बाद एक बार फिर से पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 यानी अपस्पा को वापस लेने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पहले ही कई नागरिक संगठन और इलाके के राजनेता वर्षों से अधिनियम की आड़ में सुरक्षाबलों पर ज्यादी का आरोप लगाते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोलौ चलाने का भी अधिकार होता है, इसलिए इसमें मानवाधिकार हनन की आशंका हमेशा बनी रहती है। अमूमन अपस्पा के कारण सैन्यबलों की ज्यादतियों को राजनैतिक शह मिल जाती है, लेकिन नगालैंड में पुलिस ने ही सैन्य बलों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने अपस्पा को हटाने की मांग की है। नार्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ) ने कहा कि अगर केंद्र पूर्वोत्तर के लोगों के कल्याण और कुशलता के बारे में चिंतित है तो उसे कानून को निरस्त करना चाहिए। वहाँ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएसयू) के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठोर और अलोकतांत्रिक अपस्पा को निरस्त किया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के इन लोगों की सलाह पता नहीं केंद्र सरकार तक पहुंचती है या नहीं। वैसे यह तय है कि सरकार का मनमाना रवैया और सब कुछ ठीक होने का ऊपरी दिखावा कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक आम जनजीवन में उथल-पुथल मचा चुका है। सशक्त सरकार की असली ताकत सैन्य बलों से नहीं, जनता की सख-शांति से होती है।

कब मिलेगा देश को दलित खरबपति उद्योगपति भी

आर.के. सिन्हा

याद रख ल कि भारत अपन का पूर्ण रूप से विकासित हान का दावा
उस दिन ही कर सकेगा जब हमारे यहां होंगे हजारों की संख्या में दलित
उद्योगपति/ आंतर्ज्ञानिक। हमारे यहां वैसे तो दलित राष्ट्रपति, राज्यपाल
मुख्यमंत्री, मंत्री वगैरह बन ही चुके हैं। विज्ञान, शिक्षा, खेल वगैरह क
दुनिया में भी दलित समाज से संबंध खने वाले नौजवान बेहतरीन प्रदर्शन
कर रहे हैं। लेकिन, अभी भी हमें अरबपति-खरबपति दलित उद्यमियों दे
सामने आने का इंतजार है। अच्छी बात यह है कि दलित नौजवान कारोबार
की दुनिया में अपने लिए अब जगह बनाने लगे हैं। उन्हें मोदी सरकार क
खुली अर्थव्यवस्था में भरपूर अवसर मिल रहे हैं। वे उसका लाभ लेकर
अब नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देने लगे हैं। उम्मीद करनी चाहिए
कि आने वाले समय में हमें कोई अरबपति दलित उद्यमी भी मिल ह
जाएगा। वैसे यह सामान्य बात तो नहीं है। जिस समाज का सदियों तक
शोषण ही हुआ हो उसने बिजनेस जैसे प्रतिस्पृशी क्षेत्र में अब अपनी इच्छाओं
लिखनी चालू कर दी। आगरा के रहने वाले रवीश पीपल उन दलित
उद्यमियों में हैं जो नौजवानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। वे रोजगार दे रहे ह
हैं। रवीश फुटवियर बिजनेस से जुड़े हैं। उन्हें दुनिया भर की फुटवियर
कंपनियां अपनी मांग के अनुसार माल बनाने का ॲडर देती हैं। रवीश
पीपल भारत के फुटवियर उत्पादकों को डिजाइन, तकनीकी और मार्केटिंग
की सलाह देते हुए उन कंपनियों को माल की सप्लाई करते हैं जहां से
उन्हें ॲडर मिलता है। उनकी कंपनी में सभी जातियों के मुलाजिम हैं।
वहां सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है।

यकीन मानिए कि दलित महिलाएं भी अब उट्टरी बन रही हैं। मुंबई की कल्पना सरोज का उदाहरण लीजिए। मुझे उनकी संघर्ष भरी कहानी बहुत प्रभावित करती है। वो कमानी ट्यूब्स की अध्यक्षा हैं। वे कहती हैं कि मोदी सरकार की उदार आर्थिक नीति से उन्हें लाभ मिला है। सरोज 1980 के दशक में अकोला से मुंबई आ गई। तब तक आर्थिक उदारीकरण आने में कुछ साल शेष थे। सरोज मुंबई में दर्जी का काम करके रोजाना छोटी-सी रकम कमाने लगी। फिर उन्होंने बैंक लोन लेकर फर्नीचर बदुकान शुरू कर दी। यहां भी काम चला तो सरोज ने 1997 में मुंबई में एवं

ममता बनर्जी के प्रयासों को हल्के में लेना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है

ललित गर्ग

कहा था कि जब आधा टाइम विदेश में रहेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे प्रशांत किशोर राहुल गांधी और कांग्रेस को लगातार धेरते रहे हैं। पिछले दिनों, सोशल मीडिया पर एक सवाल-जवाब के सत्र के दौरान उन्होंने कहा था कि आने वाले सालों में बीजेपी, भारतीय राजनीति के केंद्र में बनी रहेगी चाहे वह जीते या चाहे हारे। प्रशांत किशोर ने कहा था विजैसे शुरूआती 40 वर्षों में कांग्रेस के साथ हुआ, वैसा ही भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा था, ह्लादिकृत राहुल गांधी के साथ है कि वे सोचते हैं विभिन्न बस कुछ वक्त की बात है और लोग बीजेपी को उखाड़ फेकेंगे। तो, ऐसे अभी नहीं होने जा रहा है हावह सच भी है। लेकिन कांग्रेस को अपने खोयी जमीन को पाने के लिये सीधा-सरल गणित नहीं बैठाना है, बल्कि कठोर परिश्रम करना होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कोरी बयानबाजी एवं नरेन्द्र मोदी के विरोध से खोयी जमीन नहीं मिलती बल्कि वह और रसातल में जायेगी। कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी दिशाही-राजनीति से न केवल अपनी पार्टी को कमज़ोर किया है, बल्कि विषय को भी नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस को पर्दे के पीछे से चला रहे राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर उनके सहयोगी-समर्थक चाहे जो दावा करें वह हर दृष्टि से निष्प्रभावी हैं। राजनीति में इतना लंबा समय बिताने वे बाद भी वह बुनियादी राजनीतिक परिपक्वता हासिल नहीं कर सके हैं उनके लिए राजनीति का एक ही मकसद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोसना। उन्होंने सस्ती नोरेबाजी को ही राजनीति समझ लिया है। आज तुण्मूल कांग्रेस प्रमुख एवं प्रशांत किशोर के बदले हुए स्वर हैं तो इसके लिए एक बड़ी हड़तक कांग्रेस ही जिम्मेदार है। वह अपनी दयनीय दशा और बिखराव के लिए अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती।

विडम्बना तो यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपनी इस दुर्दशा पर न चिन्तन-मंथन करता है और न अपनी कमियों एवं गलतियों को स्वीकारता है। राहुल ही नहीं, कुछ इसी तरह की राजनीति प्रियकांग गांधी भी कर रहे हैं। भल ही कांग्रेस में राहुल और प्रियकांग को करिश्माई नेता बताने वाले की कमी न हो, लेकिन सच यही है कि ये दोनों नेता अपनी तमाम सक्रियता के बावजूद कहीं कई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। वास्तव में इसीलिए कांग्रेस तेजी के साथ रसातल में जा रही है। यह कांग्रेस वे लगातार कमज़ोर होते चले जाने का ही कारण है कि उसके नेता अन्दर दलों की शरण में जा रहे हैं। पंजाब एवं राजस्थान के कांग्रेसी तनाव वे लम्बे समय से हल नहीं हो पाने के पीछे राहुल की अपरिक्वत राजनीतिक सोच ही है। राहुल गांधी को चाहिए था कि पंजाब के मामले में सिद्ध करें।

मर्पित करेंगे चिकित्सा

के लिए तरसता पूर्वाचल दशकों से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा। करीब चार दशकों तक जापानी इंसेफ्लाइटिस यहां के हजारों बच्चों को हर वर्ष निगलता रहा। सरकारें बदलती रहीं मगर किसी ने सुध तक नहीं ली। नवजात शिशुओं को खोने की अपार पीड़ियां की लड़ाई योगी ने सांसद के रूप में संसद से लेकर सड़क तक लड़ी पर तत्कालीन नीति निर्मार्ताओं के कानों तक आवाज नहर्छ पहुँची। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही परिवृश्य बदलने लगा। उन्होंने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ न सिर्फ जंग छेड़ी, बल्कि समन्वित प्रयासों से इस महामारी पर नियंत्रण कर लिया गया। यह पूर्वाचल के लोगों के लिए बड़ा सुअवसर है कि प्रधानमंत्री मोदी सात दिसम्बर को गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में स्थापित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की नौ लैब्स को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये लैब्स जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारगर परीक्षण और शोध पर कार्य करेंगी। यह राज्य स्तरीय वायरस प्रशिक्षण लैब कोविड-19 की जांच और शोध के साथ अन्य विषाणु जनित बीमारियों पर शोध कार्य करेगा।

अब प्रदेश में दो एम्स संचालित हैं। एक गोरखपुर और दूसरा रायबरेली में। वर्ष 2007 में रायबरेली एम्स की स्वीकृति मिली लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव इसके संचालन में देरी हुई। मोदी-योगी की जोड़ी बनते ही प्रदेश में स्थापित दोनों एम्स विश्वस्तरीय मानक से सुसज्जित हुए और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवकों के नए युग की शुरूआत हुई। इस जोड़ी को ही एम्स के संचालन का श्रेय जाता है। वहीं, जिस बीमारी की आहट मात्र से ही पूरा परिवार हिल जाता हो, उस कैंसर के इलाज के लिए वाराणसी में देश का दूसरा बड़ा कैसर हॉस्पिटल 'महामना कैसर संस्थान' भी मरीजों के इलाज के लिए खोल दिया गया है। 2017 में प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया। योगी सरकार आज 'एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के 59 जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज क्रियाशील है। 16 जनपदों में ढढ और मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश में पहले आयुष विश्वविद्यालय का गोरखपुर में शिलान्यास किया गया है और अब इसका नाम 'योगी योगी विश्वविद्यालय' है। इसके में अन-

छलांग लगा। उन्हांना नाइट म इलाक्ट्रिक स्कूटर आर माटर साइकिल का निर्माण करने वाली इकाई स्थापित की। उन्हें इस बाबत आसानी से लोग मिल भी गया। अब उनकी कंपनी के देशभर में डीलर हैं। उनका कामकाज बेहतरीन ढंग से चल रहा है। वे मानते हैं कि पेट्रोल-डीजल की निरंतर बढ़ने वाली कीमतों को देखते हुए आने वाला सम

इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटर साइकिल और कारों का होगा। बाबा साहेब अंबेडकर के गृह प्रदेश महाराष्ट्र में हजारों दलित नौजवान सफल उद्यमी बन चुके हैं। उनका जीवन स्तर भी तेजी से बदल रहा है। वे सिर्फ नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थानों में अपने लिए आरक्षण भर कर ख्वाहिश नहीं रखते। वे बिजनेस की दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। अफसोस कि उत्तर भारत के मायावती और अखिलेश यादव जैसे घनघोर जातिवादी नेता दलित और पिछड़ी जातियों से आने वाले युवाओं का आरक्षण जैसे सवालों में ही उलझा कर रखना चाहते हैं। हालांकि उनका पकड़ भी अब कमजोर होती चली जा रही है। बेशक, कोई भी समाज जैसे कठिन दौर से गुजरता है, संघर्ष करता है, आगे चलकर तो तरक्की हीं करता है। मारवाड़ियों को ही लें। ये राजस्थान-गुजरात की सूखी और बंजर धरती और मरुस्थल में पैदा हुए। अब देश के अनेकों बड़े उद्योगपतियां मारवाड़ी समाज से ही आते हैं। पारसियों को देखिए जो ईरान से भागके आए, सिंधी जो सिंध छोड़कर आए। इन सबने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और संपन्न बने। देश विभाजन ने हजारों नौजवानों को आत्रप्योनन बनाया था। पाकिस्तान से 1947 में भारत आ गए अनेकों हिन्दू और सिख नौजवानों ने नए-नए कारोबार चालू करके अपने लिए जगह बनाई थी। विपरीत हालात में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनमें से कई आगे चलकर ब्रजमोहन मुंजाल (हीरो गुप्त), महाशय धर्मपाल गुलाटी (एमडीएच मसाले), गैनक सिंह (अपौलो टार्स), एचसी नंदवाल (एस्कोटर्स) बने। इन्होंने साबित किया कि वे विपरीत हालात में खड़े हो सकते हैं। अब दलितों का समय है, दलित व्यापार में अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ रहे हैं। एक शेर से मैं अंत करना चाहूँगा—इस तरह तय कर्तव्य है हमने मर्जिलें, गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले।

प्रयागराज, बुधवार
08. 12. 2021

06

डॉ. महेंद्र कुमार सिंह

बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। लोगों को चिकित्सा पर होने वाले खर्चों से राहत देने के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में 6 करोड़ 47 लाख लोगों को बीमा कवर दिया गया है। इसके साथ ही 42.19 लाख लोगों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा कवर सुनिश्चित किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य शिक्षा पर भी योगी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में एमबीबीएस की 938 सीटें बढ़ाई गई हैं तथा केंद्र सरकार से 900 सीटें बढ़ाए जाने की अनुमति शीघ्र मिलने की संभावना है। एमडी एवं एमएस में 127 सीटों की वृद्धि की गई है। चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही 1104 भारतीय जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

योगी सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की इंडिया रैकिंग में एसजीपीजाई 5वें, बीएचयू 7वें, केजीएमयू, लखनऊ 9वें तथा एएमयू 15वें स्थान पर है। योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कोरोना महामारी का बेहतर प्रबंधन किया, टीकाकरण में भी अग्रणी भूमिका में है। 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक डोज तथा 5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी के लोक कल्याण की प्रतिज्ञा का ही सुफल है कि आज उत्तर प्रदेश अपने लोगों को उनके नजदीक ही उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सफलता हासिल कर रहा है। राजनीति, गोरखपीठ के संतों के लिए सिद्धि नहीं, बल्कि लोक-साधना का माध्यम है। उन्होंने राजनीति को लोक सेवा व कल्याण का माध्यम बनाया है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग इसे पूरी शिरदि से माटपांडी का रहे हैं।

1 राद्रा स नहूस ना कर रह ह ।

कैसे करें अनलॉकिंग को लॉक

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कड़ कदमों और भारत में समय पर घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण, हम कोरोना महामारी की पहली लहर से आसानी से निपटने में सक्षम रहे थे। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.एस.एस.आर आदि जैसी महाशक्तियों को इस कोरोना महामारी से निपटने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, भारत में समय पर लॉकडाउन ने भारत को इस जानलेवा महामारी के दुष्परिणामों को चखने से बचा लिया। प्रथम चरण में इस महामारी के बहुत छोटे असर के कारन कई लोगों ने लॉक डाउन पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। यद्यपि भारत सरकार को कुछ और अवधि के लिए लॉक डाउन जारी रखना चाहिए था, तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण, अनलॉकिंग जल्दबाजी में किया गया था। लोगों के

अस्तित्व के कारण, अनलोकगत जटिलोंजा में किया नवी था। लगान के लिए, सो.ए.ए. का विरोध खुद को कोरोना महामारी से बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। कोरोना महामारी के खिलाफ आवाज उठाने और स्वयं के अस्तित्व को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगाना था।

और इसका दुष्परिणाम अपरिहार्य था और वो इस देश में हुआ भी। लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए बहुत जल्दी में थे। वे सरकार पर इस तरह आरोप लगा रहे थे मानो उन्हें बेवजह कैद करके रखा गया हो। नतीजा यह हुआ कि दूसरी लहर में भारतीयों ने भी जानलेवा कोरोना वायरस का स्वाद चखा। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है कि किसी शहर में खुलेआम घूमाना दूर की संभावना बन गया थी। देश में लगभग हर व्यक्ति ने कम से कम एक व्यक्ति को खोया हीं होगा, जिससे वह परिचित था। हर तरफ सिर्फ अप्पातालों के इमज़ज़ेंसी वाहनों की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर कोई भी सरकार इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान स्वयं सुनिश्चित नहीं कर सकती। इस देश पर कोरोना का कितना विनाशकरी प्रभाव पड़ा है। परन्तु ऐसा लगता है कि लोगों ने कोई सबक नहीं लिया है। कोरोनावायरस का ओमाइक्रोन संस्करण हाल ही में एक खतरा बना हुआ है। हमने यह अनलॉकिंग एक बड़ी कीमत पर हासिल की है। अब समय आ गया है कि इस अनलॉकिंग को हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाए। इस कोरोनावायरस के ओमाइक्रोन नवीनतम संस्करण से लड़ने के लिए सरकार और लोगों को बड़े पैमाने पर एक साथ आना होना। अन्यथा, इस बात की पूरी संभावना है कि यह अनलॉकिंग फिर से अनलॉक हो जाएगी, और हमें अपने आप को फिर से अपने घर के अंदर बंद करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा।

